

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान का 40वाँ संरक्षण रिज़र्व : खेजड़ली कलाँ
2.	राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह - 2026
3.	नवगठित 8 जिलों में राजीविका जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों का गठन
4.	राजस्थान युवा नीति - 2026
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 'ग्रेटीट्यूड ट्री पहल' 2. 'अपना खाता' मोबाइल ऐप 3. 'मन की बात' कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में राज्य के रामसर गाँव का जिक्र 4. नागौर पशु मेला - 2026 5. शेखावाटी फेस्टिवल - 2026 (सीकर) 6. इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी अवॉर्ड्स 2026 : डॉ. सालख खान 7. न्यायमूर्ति पानाचंद जैन का निधन 8. राष्ट्रीय मतदाता दिवस - राज्य स्तरीय समारोह
6.	16वाँ भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, 2026
7.	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025
8.	बैक्ट्रियन ऊँट
9.	अगरवुड
10.	ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex)
11.	ह्यूमनॉइड रोबोट : ASC अर्जुन
12.	गल्फूड, 2026
13.	चौथी औद्योगिक क्रांति- IR-4.0 केन्द्र
14.	77वाँ गणतंत्र दिवस, 2026
15.	राज्यपालों के विवेकाधिकार बनाम निर्वाचित सरकारों के अधिकार



## राजस्थान का 40वाँ संरक्षण रिज़र्व : खेजड़ली कलाँ

### चर्चा में क्यों?

- 17 दिसंबर, 2025 को राजस्थान वन विभाग ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम - 1972 की धारा 36A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर के खेजड़ली कलाँ को राज्य का 40वाँ संरक्षण रिज़र्व घोषित किया।



### मुख्य बिन्दु:

- यह संरक्षण रिज़र्व जोधपुर जिले की लूणी तहसील में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 150.85 हैक्टर है।

--2--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



## राजस्थान में स्थित संरक्षण रिज़र्व (40) :

क्रमांक	संरक्षण रिज़र्व का नाम	ज़िला
1.	बीसलपुर संरक्षण रिज़र्व	टोंक
2.	जोहड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर संरक्षण रिज़र्व	बीकानेर
3.	सुंधामाता संरक्षण रिज़र्व	जालोर, सिरोही
4.	गुढ़ा विश्रोइयाँ संरक्षण रिज़र्व	जोधपुर
5.	शाकम्भरी संरक्षण रिज़र्व	झुँझुनूँ, सीकर
6.	गोगेलाव संरक्षण रिज़र्व	नागौर
7.	बीड़ संरक्षण रिज़र्व	झुँझुनूँ
8.	रोटू संरक्षण रिज़र्व	नागौर
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिज़र्व	कोटा
10.	जवाई बाँध संरक्षण रिज़र्व	पाली
11.	बांसियाल खेतड़ी संरक्षण रिज़र्व	झुँझुनूँ
12.	बांसियाल - खेतड़ी बागोर संरक्षण रिज़र्व	झुँझुनूँ
13.	जवाई बाँध तेंदुआ संरक्षण रिज़र्व-II	पाली
14.	मनसा माता संरक्षण रिज़र्व	झुँझुनूँ
15.	रणखार संरक्षण रिज़र्व	जालोर
16.	शाहबाद संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
17.	शाहबाद तलहटी संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
18.	बीड़घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिज़र्व	भीलवाड़ा
19.	बाघदरा मगरमच्छ संरक्षण रिज़र्व	उदयपुर
20.	वाड़ाखेड़ा संरक्षण रिज़र्व	सिरोही
21.	झालाना-आमागढ़ संरक्षण रिज़र्व	जयपुर
22.	बाँझ अमली संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
23.	हमीरगढ़ संरक्षण रिज़र्व	भीलवाड़ा

--3--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213  
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



24.	खरमोर संरक्षण रिज़र्व	अजमेर
25.	कुरजां संरक्षण रिज़र्व	फलौदी
26.	रामगढ़ संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
27.	सोरसन I संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
28.	सोरसन II संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
29.	सोरसन III संरक्षण रिज़र्व	बाराँ
30.	महसीर संरक्षण रिज़र्व	उदयपुर
31.	बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिज़र्व	सीकर
32.	गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिज़र्व	अजमेर
33.	बीड़ मुहाना संरक्षण रिज़र्व - A	जयपुर
34.	बीड़ मुहाना संरक्षण रिज़र्व - B (सबसे छोटा)	जयपुर
35.	बालेश्वर संरक्षण रिज़र्व (सबसे बड़ा)	सीकर
36.	अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षण रिज़र्व	उदयपुर
37.	आसोप संरक्षण रिज़र्व	भीलवाड़ा
38.	मोकला संरक्षण रिज़र्व	जैसलमेर
39.	बुचारा संरक्षण रिज़र्व	कोटपूतली-बहरोड़
40.	खेजड़ली कलाँ संरक्षण रिज़र्व (नवीनतम)	जोधपुर

--:4:--

## राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह - 2026

### चर्चा में क्यों?

- 77वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- मुख्य अतिथि : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे।
- विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक : सत्येन्द्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, सीकर रेंज। (वर्तमान में महानिरीक्षक पुलिस CID CB)
- राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक (गृह रक्षा) : घनश्याम सिंह, उप समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान।

### अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

#### वंदे मातरम् सेल्फी और इवेंट्स में राजस्थान प्रथम स्थान पर:

- राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत राज्य ने 'वंदे मातरम्@150 पोर्टल' पर सेल्फी और वीडियो अपलोड करने में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- टॉप-10 जिलों में प्रदेश के 4 जिले शामिल : देशभर के टॉप 10 जिलों में पाली, राजसमंद, जयपुर और फलौदी शामिल रहे।

--:5:--

## नवगठित 8 जिलों में राजीविका जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों का गठन

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा नवगठित 08 जिलों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् की स्थापित 33 जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों के मॉडल पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (DPMU) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।

### मुख्य बिन्दु:

- नवगठित 8 जिले : बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, फलौदी एवं सलूंबर।
- DPMU के गठन से नवगठित जिलों में परियोजना क्रियान्वयन से जुड़ी प्रशासनिक एवं तकनीकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ आधार मिलेगा।
- साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
- यह पहल विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के आर्थिक सशक्तीकरण, आजीविका संवर्धन तथा संस्थागत मजबूती की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (DPMU) के गठन से स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को बल मिलेगा तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति, समन्वय और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

### फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

#### राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका

- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) या राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



- यह राजस्थान सोसायटी अधिनियम - 1958 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- **अध्यक्ष :** मुख्यमंत्री।

## उद्देश्य:

- ग्रामीण विकास के लिए की जा रही सरकारी और गैर-सरकारी पहलों के बीच प्रभावी अभिसरण लाना।
- स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के गठन और सुदृढीकरण में सहायता करना।
- गरीबों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--7--

## राजस्थान युवा नीति - 2026



चर्चा में क्यों?

- राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह के दौरान 12 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'राजस्थान युवा नीति - 2026' का विमोचन किया गया।



--:8:--



## मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य** : शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करना।
- इस नीति में युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और खेलों के विस्तार, लैंगिक हिंसा की रोकथाम, युवा कलाकारों के संवर्धन के साथ ही, सतत विकास में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है।

## पॉलिसी निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

1. **शिक्षा और कौशल** - नीति में युवाओं की पहुँच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बढ़ाने, उन्हें करियर परामर्श और उचित मार्गदर्शन देने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर समावेशी शिक्षा मॉडल लागू किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल कर उन्हें बदलते दौर के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
2. **रोजगार और उद्यमिता** - नीति में रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है।
3. **स्वास्थ्य और कल्याण** - नीति में युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति यह सुनिश्चित करती है कि युवा नशे से दूर रहे और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाएं। योग और ध्यान पद्धति के माध्यम से उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखकर खेलों से जोड़ा जाएगा।
4. **युवा नेतृत्व विकास** - विकसित राजस्थान की यात्रा में युवाओं को सहभागी बनाने के लिए नीति उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने पर जोर देती है। इसके माध्यम से युवाओं में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाएगी और उन्हें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा।

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



5. **सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता** - नीति यह सुनिश्चित करती है राज्य के प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। इससे सामाजिक और लैंगिक भेदभाव के बिना हर युवा को समावेशी वातावरण उपलब्ध होगा।
6. **कला और संस्कृति** - नीति के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि युवा राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, साहित्य और संस्कृति से पूरी तरह जुड़ाव बनाएं। इसी भावना के साथ युवा कलाकारों और नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा सांस्कृतिक उत्सवों व स्थानीय भाषा साहित्य को इस नीति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
7. **पर्यावरण संरक्षण** - नीति में जलवायु संरक्षण में युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देने, पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करने और हरित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
8. **संस्थागत तंत्र** - नवीन युवा नीति में एक मजबूत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है जिसमें खेल एवं युवा मामलात मंत्री के नेतृत्व में उच्च-स्तरीय समिति गठित होगी। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था से युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति में दिए गए सभी प्रवाधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

-:10:-

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की 'ग्रेटीट्यूड ट्री पहल'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>गणतंत्र दिवस - 2026 के अवसर पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 'ग्रेटीट्यूड ट्री पहल' का शुभारम्भ किया गया।</li><li><b>उद्देश्य</b> : स्वास्थ्य भवन (जयपुर) में एक सकारात्मक और भावनात्मक वातावरण को बढ़ावा देना, जो हमारे जीवन मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति को दर्शाता है।</li></ul>
2.	<p><b>'अपना खाता' मोबाइल ऐप</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने 'अपना खाता' मोबाइल ऐप का अनावरण किया।</li><li>इस ऐप के माध्यम से नागरिक 'अपना खाता' पोर्टल की राजस्व सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे।</li><li>ऐप के जरिए नामांतरण, सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकलें, जमाबंदी एवं मानचित्र से संबंधित जानकारी, आवेदनों की स्थिति, गैर-राजकीय प्रतिबंधित भूमि की रिपोर्ट, विभागीय परिपत्र एवं गिरदावरी से जुड़ी सेवाएँ मोबाइल फोन पर उपलब्ध होंगी।</li></ul>
3.	<p><b>'मन की बात' कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में राज्य के रामसर गाँव का जिक्र</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम की '130वीं कड़ी' में श्रीअन्न (मिलेट्स) के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हुए बाड़मेर के रामसर के किसानों के नवाचारों का जिक्र किया।</li><li>रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं और बाजरे को प्रोसेस करके रेडी-टू-ईट लड्डू तैयार करते हैं।</li></ul>

4.	<p><b>नागौर पशु मेला - 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>आयोजन :</b> 24 से 27 जनवरी, 2026 तक।</li><li>■ प्रतिवर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ पूर्णिमा तक मानासर (नागौर) में लोकदेवता रामदेव जी की याद में बाबा रामदेव पशु मेला भरता है। इसे नागौर मेला भी कहते हैं।</li><li>■ इसका आयोजन RTDC द्वारा किया जाता है। इसमें पशुओं की खरीद फरोख्त के साथ-साथ लाल मिर्च बाजार भी प्रसिद्ध है।</li></ul>
5.	<p><b>शेखावाटी फेस्टिवल - 2026 (सीकर)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>आयोजन :</b> 24 और 25 जनवरी, 2026</li><li>■ <b>आयोजन स्थल :</b> अर्बन हाट, सीकर।</li><li>■ <b>आयोजक :</b> राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, सीकर।</li></ul>
6.	<p><b>इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी अवॉर्ड्स 2026 : डॉ. सालख खान</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ बाड़मेर निवासी डॉ. सालख खान को इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी अवॉर्ड्स 2026 से सम्मानित किया जाएगा।</li><li>■ <b>आयोजन स्थल :</b> हैदराबाद (तेलंगाना) में आयोजित 13वें इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस (IPSC) के दौरान।</li></ul>
7.	<p><b>न्यायमूर्ति पानाचंद जैन का निधन</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पानाचंद जैन का 27 जनवरी, 2026 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।</li></ul>
8.	<p><b>राष्ट्रीय मतदाता दिवस - राज्य स्तरीय समारोह</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>आयोजन स्थल :</b> 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) का राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में किया गया।</li><li>■ <b>राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय :</b> माय इंडिया, माय वोट।</li><li>■ <b>नोट :</b> राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान एवं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2026 के उपलक्ष में चित्रकला कार्यशाला का आयोजन जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में किया गया।</li></ul>

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### 16वाँ भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, 2026

#### चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेरलेयेन ने यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन में संयुक्त रूप से भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (भारत-यूरोपीय संघ FTA) को संपन्न करने की घोषणा की।



#### मुख्य बिन्दु:

- आयोजन:** 27 जनवरी, 2026, नई दिल्ली।
- परिणाम:** भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता।
- यूरोपीय संघ, भारत का 22वाँ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) साझेदार है।
- सरकार ने वर्ष 2014 से मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, EFTA, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं और न्यूजीलैंड के साथ समझौते की घोषणा की।
- वर्ष 2025 में भारत ने ओमान और यूके के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।

--:13:--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



## समझौते के मुख्य बिंदु:

क्रमांक	दस्तावेज	क्षेत्र
1.	2030 की ओर : भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा।	भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला व्यापक दस्तावेज।
2.	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के समापन पर संयुक्त घोषणा।	व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्त।
3.	RBI और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ESMA) के मध्य समझौता।	
4.	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर प्रशासनिक व्यवस्था।	
5.	सुरक्षा और रक्षा साझेदारी	रक्षा और सुरक्षा।
6.	भारत-यूरोपीय संघ सूचना सुरक्षा समझौते हेतु वार्ता की शुरुआत।	
7.	मोबिलिटी पर सहयोग ढाँचा	कौशल विकास और मोबिलिटी।
8.	भारत में कौशल गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के पायलट लीगल गेटवे कार्यालय स्थापना की घोषणा।	
9.	आपदा जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन कार्यवाही में सहयोग संबंधी NDMA और यूरोपीय नागरिक सुरक्षा एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय के मध्य प्रशासनिक व्यवस्था।	आपदा प्रबंधन।

-:14:-



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213  
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



10.	ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन।	स्वच्छ ऊर्जा।
11.	वर्ष 2025-2030 की अवधि के लिए भारत-यूरोपीय संघ के वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते का नवीनीकरण।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं नवाचार।
12.	होराइजन यूरोप कार्यक्रम के साथ सहयोग समझौते में भारत के प्रवेश के लिए प्रारंभिक वार्ता की शुरुआत।	
13.	भारत-यूरोपीय संघ त्रिपक्षीय सहयोग के तहत चार परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने का समझौता। इनमें शामिल हैं- डिजिटल नवाचार और महिला एवं युवा कौशल केन्द्र; कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए सौर आधारित समाधान; प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अफ्रीका तथा हिंद प्रशांत और कैरेबियन क्षेत्र के छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में सौर आधारित सतत ऊर्जा परिवर्तन।	कनेक्टिविटी।

- **भारत-यूरोपीय संघ व्यापार:** वर्ष 2024-25 में वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (6.4 लाख करोड़ रुपये: निर्यात व 5.1 लाख करोड़ रुपये: आयात)।
- भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो वैश्विक घरेलू उत्पाद के 25% के बराबर और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा है।
- समझौते के लागू होने पर लगभग 33 बिलियन डॉलर के निर्यात पर टैरिफ को 10% तक कम कर दिया गया है।

--:15:--

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025 के तहत कार्बन गहन उद्योगों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के दूसरे दौर को अधिसूचित किया है।

#### मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** GEI लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित वैधानिक नियम है, जिनका उद्देश्य औद्योगिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य क्षेत्र विशिष्ट ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य निर्धारित करना और भारत की कार्बन ट्रेडिंग योजना (CCTS) को क्रियान्वित करना है।
- लागू:** 9 अक्टूबर, 2025
- यह भारत का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी औद्योगिक उत्सर्जन तीव्रता नियम है।
- यह कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023 पर आधारित है।
- नोडल मंत्रालय :**

नियम अधिसूचना	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कार्बन क्रेडिट जारी करना और गणना करना	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
अनुपालना प्रवर्तन और दंड	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



- दूसरे दौर में शामिल क्षेत्र: पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इकाइयाँ, वस्त्र क्षेत्र (कताई, प्रसंस्करण, मिश्रित इकाइयाँ) और द्वितीयक एल्युमीनियम।
- इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL ONGC नुमालीगढ रिफाइनरी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रियायंस इंडस्ट्रीज जैसे निजी क्षेत्र के उपक्रम सहित 25 औद्योगिक इकाइयाँ।
- नोट: प्रथम दौर में शामिल क्षेत्र (अक्टूबर, 2025): एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोरक्षार, लुगदी और कागज उपक्रम।
- इस प्रकार अब तक कुल 8 अत्यधिक कार्बन-गहन उद्योग एक अनिवार्य उत्सर्जन कटौती व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं।

## प्रमुख विशेषताएँ:

1. आधारभूत वर्ष : वर्ष 2023-24 अनुपालना लक्ष्य वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित किए गए।
2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता : वैश्विक तापन क्षमता के आधार पर सभी ग्रीनहाउस गैसों को कवर करते हुए, उत्पादन की प्रति इकाई t CO<sub>2</sub>e के रूप में व्यक्त लक्ष्य।
3. कार्बन बाजार : CCTS के माध्यम से कवर की गई संस्थाओं को भारत के घरेलू कार्बन बाजार के अंतर्गत लाया जाता है।
4. अनुपालन नहीं होने पर दंड का प्रावधान : पर्यावरण क्षतिपूर्ति (उस अनुपालना वर्ष के औसत कार्बन क्रेडिट मूल्य का दोगुना।
- भुगतान अवधि: 90 दिनों में भुगतान करना अनिवार्य।
5. उत्सर्जन कटौती लक्ष्य और समयसीमा: इन क्षेत्रों में 2023-24 के आधार स्तर की तुलना में वर्ष 2026-27 तक 3 से 7% की सीमा में विशिष्ट कटौती लक्ष्य पूरा करने की अपेक्षा की गई है।

-:17:-

## नियमों का महत्त्व :

1. **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन (पेरिस समझौता (वर्ष 2015)) :** देशों को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
2. **बाध्यकारी ढाँचा:** यह नियम कार्बन गहन उद्योगों के लिए भारत के पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

## अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

### कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023 :

- **शुरुआत:** केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 28 जून, 2023 को।
- **नोडल एजेंसी :** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया।
- **पर्यवेक्षक निकाय:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) : नियमों के अनुपालना की निगरानी और गैर अनुपालना के लिए मौद्रिक निर्धारण।
- **ट्रेडिंग तंत्र:** यदि कोई कार्बन उत्सर्जक उद्योग कानूनी उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन करता है तो उसे उन सत्यापित परियोजनाओं से क्रेडिट खरीदना होगा।
- इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, मीथेन कैप्चर, कार्बन कैप्चर तकनीक और वनीकरण या पुनर्वनीकरण की पहल शामिल है।
- **क्षेत्रीय कवरेज:** प्रारंभ में भारत के कुल उत्सर्जन के 16% हिस्से वाले क्षेत्रों (लौह, इस्पात और एल्युमीनियम) को लक्षित किया गया।

## बैक्ट्रियन ऊँट



### चर्चा में क्यों?

- गणतंत्र दिवस परेड-2026 में गलवान और नुब्रा नामक दो बैक्ट्रियन ऊँटों ने पहली बार कर्त्तव्य पथ पर मार्च किया।



### मुख्य बिन्दु:

#### बैक्ट्रियन ऊँट - अतिरिक्त जानकारी-

- इसका नाम बैक्ट्रिया, मध्य एशिया के एक प्राचीन क्षेत्र से पड़ा है।
- यह ठण्डे मरुस्थलों में रहने वाला सम-खुर वाला जानवर है।
- **पर्यावास:** मूलतः मध्य एशिया के शुष्क और ठण्डे क्षेत्र जैसे - गोबी और तकला मकान मरुस्थल।
- भारत में लगभग 300-400 बैक्ट्रियन ऊँट है जो लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** इसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं, जिसमें वसा जमा रहती है।
- **जलवायु अनुकूलन:** इसके शरीर पर सर्दियों में घने फर उग आते हैं। यह माइनस 30°C से 40°C तक के तापमान को सहन कर सकता है।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN लाल सूची के अनुसार यह प्रजाति क्रिटिकली एंडेंजर्ड (गंभीर रूप से संकटग्रस्त) है।

--:19::--

## भूगोल

### अगरवुड

#### चर्चा में क्यों?

- केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा में अगरवुड वैल्यु चेन डवलपमेंट स्कीम की आधारशिला रखी।



#### मुख्य बिन्दु:

#### अगरवुड अतिरिक्त जानकारी-

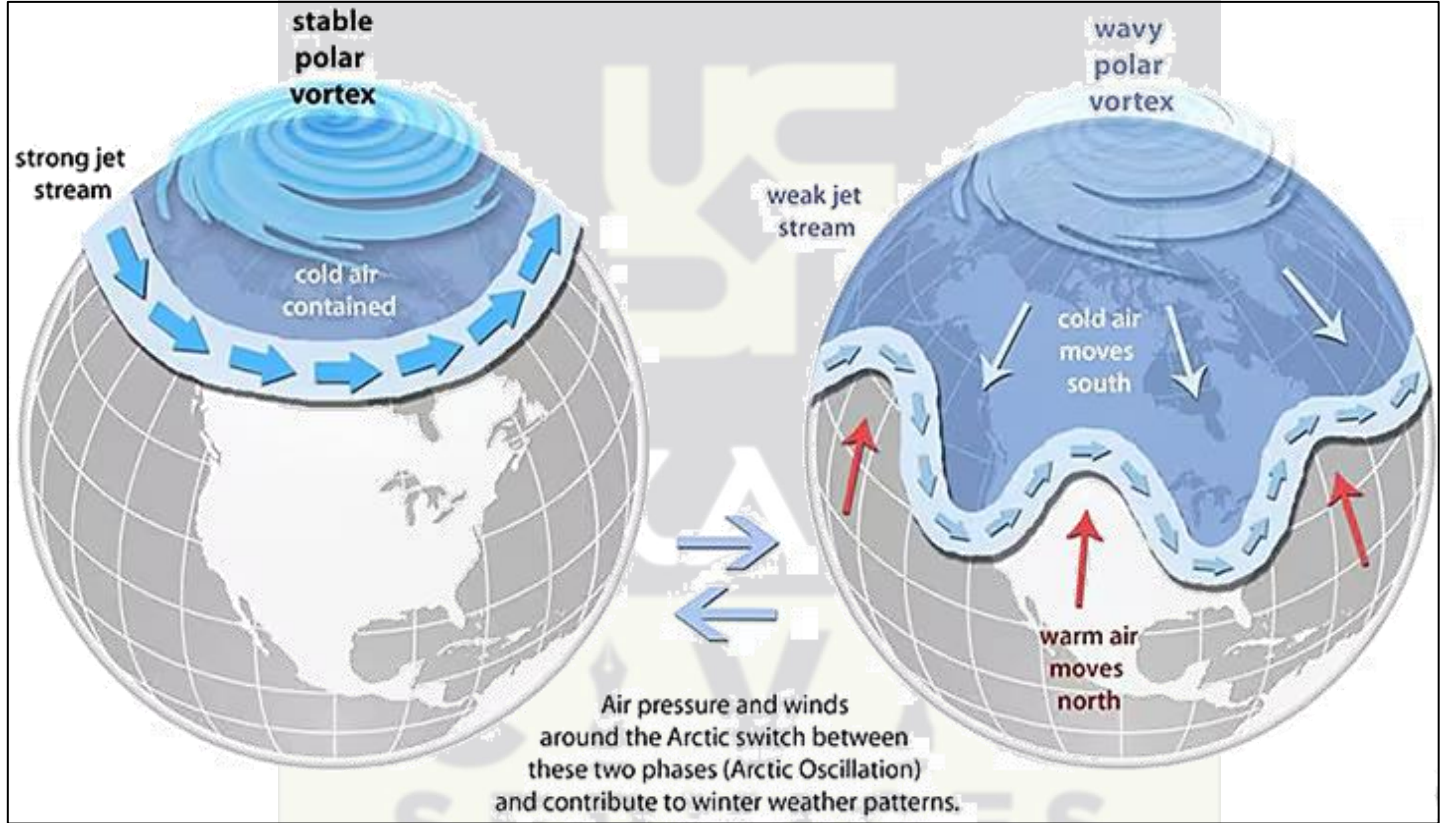
- अगरवुड एक दुर्लभ, सुगंधित लकड़ी है। इसका उपयोग उच्च मूल्य वाले इत्र के तेल, अगरबत्ती और पारंपरिक औषधियाँ बनाने में किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्ण कटिबंधीय उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें त्रिपुरा और उत्तर-पूर्वी भारत के अन्य भाग शामिल हैं।

--:20:--

## ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex)

### चर्चा में क्यों?

- ध्रुवीय भंवर के दक्षिण की ओर विस्तार के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक ठंड की स्थिति देखी जा रही है।



### मुख्य बिन्दु:

#### ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) के बारे में

- **परिभाषा:** ध्रुवीय भंवर एक बड़ा और स्थायी निम्न दाब वाला क्षेत्र है। इसमें अत्यधिक ठंडी वायु राशि होती है। यह पोलर-फ्रंट जेट स्ट्रीम द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर सीमित रहता है।
- **पोलर-फ्रंट जेट स्ट्रीम:** यह पूर्व की ओर बढ़ने वाली तीव्र वेग युक्त समतापमंडलीय हवाओं की एक पट्टी है। यह पट्टी मध्य-अक्षांशों में गर्म उष्णकटिबंधीय हवा को ठंडी ध्रुवीय हवा से अलग करती है।
- **घूर्णन की दिशा:** यह उत्तरी ध्रुव पर वामावर्त और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणावर्त घूमता है।

-:21:-

## निर्माण के उत्तरदायी कारक:

- तापमान प्रवणता (ठंडे ध्रुवीय और गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच)
- पृथ्वी का घूर्णन (कोरिओलिस बल)
- दबाव प्रवणता बल।
- जेट स्ट्रीम की परस्पर क्रिया।
- **स्थिरता:** जब यह भंवर मजबूत और स्थिर होता है, तो यह जेट स्ट्रीम को एक तंग व गोलाकार पथ पर बनाए रखता है। इससे ठंडी हवा उत्तर में फंसी रहती है और गर्म हवा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है।
- **अस्थिरता:** जब यह कमजोर हो जाता है, तो यह लहरदार हो जाता है। इससे दक्षिण में अत्यधिक ठंड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

## ध्रुवीय भंवर के प्रकार

- **क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** यह 10 किमी. से 15 किमी. की ऊंचाई पर निर्मित होता है, जहाँ मौसम संबंधी अधिकतर घटनाएँ घटित होती हैं।
- **समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** यह 15-50 किमी की ऊंचाई पर बनता है। यह सर्दियों के मौसम में सबसे मजबूत होता है।

## ध्रुवीय भंवर के प्रभाव

- **ठंडा मौसम:** आर्कटिक के तेजी से गर्म होने के कारण ध्रुवों और मध्य-अक्षांशों के बीच तापमान का अंतर कम हो रहा है। इससे भंवर अधिक अस्थिर हो सकता है, जिससे गंभीर शीत लहरों की आवृत्ति बढ़ सकती है।
- **ओज़ोन का क्षय:** भंवर में फंसी ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन क्षरण को तीव्र करती है। इससे ओज़ोन छिद्र बनता है।
- **भारत पर प्रभाव:** ध्रुवीय भंवर और भारतीय मौसम के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन आर्कटिक हवाएँ पश्चिमी विक्षोभ सहित विभिन्न मौसम प्रणालियों को प्रभावित कर रही हैं।

## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

### ह्यूमनॉइड रोबोट : ASC अर्जुन

#### 📢 चर्चा में क्यों?

- भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर 'ASC अर्जुन' नामक एक मानवरूपी रोबोट तैनात किया।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

- **परिचय :** यह एक AI संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को स्टेशन की निगरानी, भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सहायता के लिए तैनात किया गया है।
- **विकास :** तकनीकी टीम, भारतीय रेलवे, विशाखापट्टनम (स्वदेशी रूप से डिज़ाइन व निर्मित)।

#### रोबोट के कार्य :

1. सुरक्षा व निगरानी।
2. रीयल टाइम अलर्ट।
3. आपातकालीन प्रतिक्रिया।
4. मानवीय संपर्क।

## आर्थिक परिदृश्य

### गल्फूड, 2026

#### चर्चा में क्यों?

- विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी, गल्फूड, 2026 में कंट्री पार्टनर के रूप में भारत ने अपनी सशक्त और रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई।



#### मुख्य बिन्दु:

- आयोजन : 26 से 30 जनवरी, 2026 तक।
- आयोजन स्थान: दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई एक्सपो सिटी (पहली बार 2 स्थानों पर आयोजन)।
- भारत की भूमिका: कंट्री पार्टनर।

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



## मुख्य उद्देश्य :

- विश्व की खाद्य टोकरी के रूप में भारत की क्षमता प्रदर्शित करना, टिकाऊ और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना।
- **प्रतिभागी** : APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के तहत कृषि निर्यात स्टार्टअप (एपेडा की भारती पहल के तहत 8 स्टार्टअप्स), किसान उत्पादक संगठन और 25 राज्यों के प्रतिनिधि।

## भारत द्वारा प्रदर्शित उत्पाद:

1. बासमती चावल।
  2. 10 से अधिक भारतीय GI-टैग वाली चावल की किस्में।
  3. प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद।
  4. बाजरा, मूंगफली, चाय, मसाले, हल्दी, जैविक उत्पाद।
  5. फल व सब्जियाँ।
- **नोट**: संयुक्त अरब अमीरात, एपेडा के निर्धारित उत्पादों का सबसे बड़ा बाज़ार है और खाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जो भारत के कृषि निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है।

--:25:--

## चौथी औद्योगिक क्रांति- IR-4.0 केन्द्र

### चर्चा में क्यों?

- विश्व आर्थिक मंच ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति (IR 4.0) केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की।



### मुख्य बिन्दु:

- इनमें से एक केन्द्र भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत में इस तरह का तीसरा केन्द्र होगा।

### IR- 4.0 क्या है-

- इस शब्द का प्रतिपादन 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने किया था।
- IR-4.0 में कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसे घटक शामिल हैं।

--:26:--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



- पिछली क्रांतियों के विपरीत IR-4.0 भौतिक, डिजिटल और जैविक प्रणालियों के बीच की सीमाओं को अस्पष्ट कर रही है।

## औद्योगिक क्रांति के चरण:-

- **पहली:** मशीनीकरण, जल शक्ति, भाप शक्ति।
- **दूसरी:** बड़े पैमाने पर उत्पादन, असेंबली लाइन, विद्युत।
- **तीसरी:** कम्प्यूटर एण्ड ऑटोमेशन।
- **चौथी:** साइबर भौतिक प्रणालियाँ।

## चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्त्व

आर्थिक संवृद्धि	-	उत्पादकता व बेहतर आपूर्ति श्रृंखला।
समावेशी विकास की क्षमता	-	डिजिटल पहुँच।
पर्यावरणीय संधारणीयता	-	स्मार्ट ग्रिड, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कम कार्बन उत्सर्जन प्रणालियाँ, बेहतर संसाधन दक्षता

## चुनौतियाँ और जोखिम

तकनीकी अंतराल	-	विकसित व विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ने का जोखिम।
कार्यबल व्यवधान	-	शारीरिक कौशल की माँग में कमी तथा तकनीकी कौशल की माँग में वृद्धि।
साइबर हमले	-	जासूसी तथा तकनीकी अवसंरचना की सुभेद्यता।
पर्यावरणीय प्रभाव	-	सेंसर्स, डेटा सेंटर, कनेक्टेड डिवाइसेस से ऊर्जा व दुर्लभ संसाधनों के उपभोग में वृद्धि।

-:27:-

## राजव्यवस्था

### 77वाँ गणतंत्र दिवस, 2026

#### चर्चा में क्यों?

- भारतीय संविधान लागू होने के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
- विषयवस्तु: वंदे मातरम् के 150 वर्ष।
- मुख्य अतिथि : एंटोनिया कोस्टा (यूरोपीय परिषद् के अध्यक्ष) व उर्सुला वॉन डेर लेयेन (यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष।)



#### मुख्य बिन्दु:

गणतंत्र दिवस : ऐतिहासिक महत्व :

- पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव: दिसंबर, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन (अध्यक्षता : जवाहरलाल नेहरू) में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया।

--:28:--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



- **पूर्ण स्वराज दिवस** : काँग्रेस अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी, 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस का लक्ष्य तय किया गया तथा वर्ष 1930 से वर्ष 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।

## संविधान सभा :

- **पहली बैठक** : दिसंबर, 1946, संविधान हॉल।
- **संविधान पूर्ण**: 26 नवंबर, 1949 (संविधान को अपनाया गया)।
- **संविधान लागू**: 26 जनवरी, 1950 (वर्ष 1930 की पूर्ण स्वराज घोषणा के सम्मान में)।

## 77वाँ गणतंत्र दिवस, 2026 :

- **झांकियाँ**: 'राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की 30 झांकियों को 'स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम्' और 'समृद्धि का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत' जैसे उप-विषयों के तहत प्रस्तुत किया गया।

राज्य/मंत्रालय/विभाग/सेना	झांकी का विषय
असम	अशरिकंडी गाँव व टेराकोटा शिल्प परंपरा ।
गुजरात	क्रांतिकारी मेडम भीकाजी कामा को समर्पित ।
महाराष्ट्र	गणेशोत्सव (तिलक) ।
उत्तर प्रदेश	बुंदेलखंड की संस्कृति ।
पश्चिम बंगाल	वंदे मातरम् (बंकिमचंद्र चटर्जी)
पंजाब	गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित ।
केरल	कोच्चि वाटर मेट्रो (भारत की पहली वाटर मेट्रो)।
तीनो सेना (सैन्य विभाग)	ऑपरेशन सिंदूर - संयुक्तता के माध्यम से विजय।
संस्कृति मंत्रालय	कलात्मक रूप : वंदे मातरम् के 150 वर्ष ।
गृह मंत्रालय	वर्ष 2001 के भुज भूकंप के बाद पुनर्निर्माण।

--:29:--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



- **पद्म पुरस्कार, 2026** : कुल 131 पद्म पुरस्कार (5 पद्म विभूषण + 13 पद्म भूषण + 113 पद्मश्री)।
- **सैन्य पुरस्कार** : अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, थल, नौ, वायु सेना पदक सहित 70 सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित।
- **PTM एवं TM पदक** : राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक (PTM) और तटरक्षक पदक (TM) प्रदान किए।
- **सेवाकर्मी**: 982 कर्मियों को वीरता व सेवा पदक।
- **जीवन रक्षक पुरस्कार** : जीवन रक्षा जैसे सराहनीय मानवीय कार्य को प्रदान किया गया।
- **नोट**: इस समारोह में नवगठित भैरव बटालियन (विशेष आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई) ने पहली बार प्रदर्शन किया।
- **नोट**: यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया (यूरोप के बाहर पहली भागीदारी)।

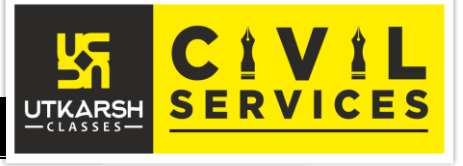
## गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित हथियार प्रणाली:

1. ब्रह्मोस व S-400
2. इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर।
3. आकाश मिसाइल प्रणाली।
4. बैटल एरे फॉर्मेट (पहली बार)।
5. 61 कैवलरी युद्धक पोशाक।
6. T-90 भीष्म टैंक व अपाचे हेलीकॉप्टर।
7. अर्जुन टैंक व प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर।
8. हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल।
9. ध्रुव (एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर)।
10. नाग मिसाइल सिस्टम व BMP दो इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल।
11. अजयकेतु ऑन-टेरेन व्हीकल, रंघ्वज रग्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम व ध्वंस्क लाइट स्ट्राइक व्हीकल।
12. रोबोटिक डॉग, मानव रहित जमीनी वाहन (UGV) व राफेल, मिग-29, सुखोई-30, जगुआर।
13. शक्तिबाण व दिव्यास्त्र।
14. हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल (LR-ASHM)।

--:30:--

# Daily Current Affairs

Date : 28 January, 2026



**अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:**

**वंदे मातरम:**

- **उत्पत्ति:** बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पहली बार वर्ष 1875 में बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ और बाद में आनंदमठ (वर्ष 1882) में शामिल किया गया।
- **राष्ट्रीय दर्जा:** 24 जनवरी, 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रीय गान होगा तथा स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
- **संविधान में उल्लेख:** भारत के संविधान में राष्ट्रीय गीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है हालांकि अनुच्छेद 51A (a) नागरिकों से संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का आग्रह करता है।

**स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका :**

- **काँग्रेस द्वारा अपनाया:** वर्ष 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने काँग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में।
- **अखिल भारतीय रूप से अपनाया:** वाराणासी अधिवेशन (वर्ष 1905)।
- **जन लामबंदी व प्रेस :** उत्तरी कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय (वर्ष 1905) व वर्ष 1906 में बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में अंग्रेजी दैनिक समाचार 'वंदे मातरम' का शुभारंभ।
- **स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा :** वंदे मातरम का पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रयोग।

**विदेशों में वंदे मातरम:**

- वर्ष 1907 में मेडम भीकाजी कामा ने भारत के बाहर पहली बार जर्मनी के स्टटगार्ड में तिरंगा झंडा फहराया उस पर वंदे मातरम लिखा था।
- अगस्त, 1909 में मदन लाल धींगरा के अंतिम शब्द (इंग्लैंड)।
- अक्टूबर, 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने वंदे मातरम नारे के साथ केपटाउन में जुलूस आरंभ किया।

--:31:--

## राज्यपालों के विवेकाधिकार बनाम निर्वाचित सरकारों के अधिकार



### चर्चा में क्यों?

- हाल के वर्षों में, कुछ राज्यों में साल के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के संबोधन को लेकर विवाद देखे गए हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में राज्य विधानसभा सत्रों के दौरान राज्यपालों द्वारा हाल ही में किए गए वॉकआउट ने राज्यपालों के विवेकाधिकार बनाम निर्वाचित सरकारों के अधिकार को लेकर संवैधानिक बहस को जन्म दिया है।
- ये घटनाएं अनुच्छेद 176 (राज्यपाल का अनिवार्य संबोधन) और अनुच्छेद 163 (मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह) की सीमाओं का परीक्षण करती हैं।

### प्रासंगिक संवैधानिक अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 175:** इसके तहत राज्यपाल को सदन (या सदनों) को किसी भी समय संबोधित करने या संदेश भेजने का अधिकार है।
- **अनुच्छेद 176:** यह राज्यपाल को अनिवार्य रूप से विशेष अभिभाषण देने का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 175 की तरह स्वैच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है।

### यह अभिभाषण दिया जाता है:

- प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में।

### चिंताएँ

- **संवैधानिक जनादेश का क्षरण:** अनुच्छेद 176(1) के तहत संबोधन से राज्यपाल का चयनात्मक पठन या वॉकआउट प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति का उल्लंघन करता है और निर्वाचित सरकार और विधानमंडल के बीच औपचारिक संचार की परिकल्पना करने वाली संवैधानिक योजना को कमजोर करता है।
- **संसदीय संप्रभुता के लिए खतरा:** नियमित कार्यकारी कार्यों में विवेकाधिकार का विस्तार करने से राज्यपाल के समानांतर प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का खतरा पैदा होता है, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार चेतावनी दी है कि यह संसदीय लोकतंत्र को खोखला कर देगा।

## राज्यपाल की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय

- **शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)** के मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, न कि स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में।
- न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसी पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से कैबिनेट की स्थापित नीति की आलोचना करना एक "असंवैधानिक गलती" है जो संसदीय प्रणाली का उल्लंघन करती है।
- **नबम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर (2016)** मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल एक औपचारिक प्रमुख है और अनुच्छेद 163 के तहत, उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, जिसका विवेक केवल विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित है।
- **तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल (2025)** के मामले में, न्यायालय ने माना कि राज्यपाल का विवेकाधिकार एक जिम्मेदार निर्वाचित सरकार को रद्द या बाधित नहीं कर सकता है।

## आगे की राह

- राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच नियमित परामर्श जैसे संस्थागत तंत्र टकराव को कम कर सकते हैं।
- **संवैधानिक पाठ और परंपराओं का पालन:** राज्यपालों को संविधान और सुस्थापित परंपराओं के अनुसार सख्ती से कार्य करना चाहिए।
- **सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिश:** दोनों आयोगों ने राज्यपालों के लिए निष्पक्ष रूप से और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।